what has happended in the House and having different interpretations about it, they should have direct access, sitting in tneir homes *to* what is happening in Par. liament. For that, I feel a great' purpose would be served if at least, to begin with, the Question Hour and fifteen minutes after that are thrown open to the general public through the television. The people would then know what is happening and how their elected representatives are discharging their responsibilities here.

Madam, there could be different interpretations about the need for such live telecast. For that, I would say that a Committee of the House could be formed which could go into the question of deciding which proceedings about a particular item on the list of business could be telecast. But, the Question Hour and 15-minutes thereafter which would cover the zero hour period normally should be covered. Such a practice, Madam, is, to a limited extent, prevnlent in some countries, and even major democracies are now taking steps to introduce live telecast of the proceedings. In view of that. Madam, I once again take this opportunity, through you, to impress upon the Government to take steps in this direction.

Thank you.

SHRI RAINI RANJAN SAHU (Bihar) : I want to associate myself with the hen. Member. I would like to add. Madam, hat the other day, two days back, what 3 speak about live telecast, even the iansad Sarniichnr in Hindi and Inslish did of depxt the correct picture of the pro- eedings here. Doordarshan does net five :? correct picture and ii does not give be correct names. Some of the names oreft -out.

So, I also associate with Pawan Kumarji at live telecast she.Id he here, and the orking of Doordashan should be streamed. For th;- .* a committee should be up.

ed for adequate relief to Bihar Earthquake Victims

डा० जगन्नाथ मिश्र (बिहार) : सभापति महोदया, विशेष उल्लेख के

लिए अनुमति दिये जाने के लिए आपका धन्यवाद । मैं कल ही बिहार से लौटा हूं । 21 अगस्त को भूकम्प से जो वहां बर्बादी हुई है, नुकसान हुआ है उसका सही चित्र अभी तक राष्ट्र के सामने सरकार के स्तर पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। 22 अगस्त को प्रधान मंत्री केन्द्रीय मंत्रियों के साथ गये थे और दरभंगा और मुंगेर का दौरा किया था । उन्होंने सहानुभूति दिखाई। वहां पर बड़ी क्षति हुई है। चार जिलों का हमने सघन दौरा किया है—दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और मादीपुरा । बीस अस्पतालों में हम गये है जहां हजारों घायल लोग अभी हैं। स्वास्थ्य मंत्री बोरा साहब वहां गये थे। उन्होंने वहां की स्थिति को स्वयं देखा है। वहां पर अभी तक उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं हुई है । जो गम्भीर रूप से घायल हैं जिन्हें विशेष उपचार चाहिए और विशेष दवायें चाहिए उन्हें वे अभी तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। लगभग दो लाख परिवार क्षतिग्रस्त हो गये हैं । कितनी बर्बादी है, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में, देखने से ही स्थिति आंकी जा सकती है । राज्य सरकार की ओर से अभी तक न तो समुचित सर्वेक्षण किया गया है, न जायजा लिया गया है और न ही केन्द्रीय सरकार के समक्ष ब्यौरा भेजा गया है। आवश्यकता इस समय यह थी कि जो क्षतिग्रस्त लोग हैं, जो बच्चे, महिलायें खुले आकाश में बिना किसी छाया के वर्षा के समय धूप के समय बाहर हैं बीमार पड़ रहे हैं। लाखों मकान ध्वस्त हो चुके हैं और जिन मकानों में दरारें पड़ गई हैं वे मकान भी बरसात के साथ-साथ गिरते जा रहे हैं। जमीन में बालू निकल आया है, कुओं में बालू भर गया है।

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

जो पीने के पानी के स्थान हैं वे अवरुद्ध हो गये हैं। सिंचाई के लिए जो नलकूप हैं सरकारी या गैर-सरकारी अथवा निजी, वे भी अवरुद्ध हो गये हैं, भर गये हैं। धान लगे हुए जो खेत हैं उनमें भी बालू भर गया है। उस इलाके की क्षति बहुत बड़ी है और उसे जब तक केन्द्र सरकार सही रूप में आंकेगी नहीं, पूरी सहानुभूति और सहायता नहीं देगी, इन लोगों की मदद नहीं हो सकती है। हमने स्वयं देखा है, सैकड़ों और हजारों लोग बड़े द्रवित हैं और बहुत दुखी हैं, उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। राज्य शासन की ओर से उन्हें पांच हजार रुपये अनुग्रह राशि के रूप में देने का एलान हुआ है जिनकी मृत्यु हुई है और प्रधान मंत्रीय जी ने अपने दौरे के क्रम में दस हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा भी की है। लेकिन अभी तक इस राशि का समुचित भुगतान सभी सम्बद्ध परिवारों को नहीं हो पाया है। जख्मी को पांच सौ रुपये देने का एलान हुआ। हमने स्वयं देखा है सहरसा के अस्पताल में, मधुबनी के अस्पताल में, मादीपुर के अस्पताल में और दरभंगा के अस्पताल में, जिनका पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है उनको ढाई सौ रुपये देने का एलान हुआ था, लेकिन हमने झंझारपुर के अस्पताल में देखा कि उनको सिर्फ 25 रु. या 50 रु. दिये गये हैं। सरकार की ओर से पांच सौ रुपये देने की घोषणा हुई थी, उनको इतनी कम रकम कैसे दी गई, इसकी जानकारी नहीं मिली है। सरकार की मंशा मदद करने की है और प्रधान मंत्री की हिदायतें भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मदद नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री वोरा ने स्वयं यह देखा है, खासकर मधुबनी के अस्पताल में देखा है। यह उन्होंने 23 तारीख को देखा है और मैं 26-27 तारीख को वहां से लौटा हूं। अस्पतालों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई सुधार नहीं हैं, रोगी इलाज के लिए पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को प्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यह बड़ा प्राकृतिक संकट है। राज्य शासन के भरोसे इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। जिन जिलों में यह हालत है, बाढ़ की मार भी दुबारा इन जिलों में पड़ रही है। दरभंगा, में, मधुबनी में, सहरसा में और मुंगेर में बाढ़ के कारण भी स्थिति गम्भीर हो गई है। इसलिए बाढ़ राहत कार्य और भूकम्प राहत कार्य समन्वित ढंग से हो सके, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में मैं भारत सरकार से दो तीन निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह कि कोई केन्द्रीय दल तुरन्त वहां वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिये भेजा जाय। दूसरा कोसी के तटबंध, कमला बालान के तटबंध प्रभावित हो गये हैं और कहीं-कहीं पर ये तटबंध भूकम्प के कारण टूट भी गये हैं। इसलिये इन तटबंधों का उचित प्रबंध किया जाना चाहिये, उनका विस्तार किया जाना चाहिये। वहां के लोग बाढ़ के कारण पिछले सालों में परेशान रहे हैं और अब उनमें और अधिक निराशा आ गई है कि तटबंधों की सुरक्षा आगे नहीं हो सकती। इसलिये लोगों के मन में भारत सरकार को विश्वास पैदा करना चाहिये तथा इन तटबंधों की मरम्मत का कार्य विशेषज्ञों की सहायता से कराया जाना चाहिये। दूसरा जिन दो लाख परिवारों के मकान पूर्णरूप से ध्वस्त हो गये हैं उनको बरसात से बचाने के लिये तारपोलीन, पोलीथीन और एसबसटस सीट देकर उनकी सहायता करनी चाहिये जिससे इन परिवारों के बच्चों और औरतों की रक्षा हो सके और पानी तथा धूप से उनका बचाव हो सके। इसके साथ ही जो

भूमिहीन हरिजन हैं, जो दूसरे गरीब लोग हैं उनके लिये इंदिरा आवास योजना का विस्तार विशेष रूप से किया जाये और ऐसे लोगों को दस हजार रुपये की विशेष सहायता दी जाये। इस इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनके मकान ध्वस्त हो गये हैं उनके लिये विशेष ऋण की व्यवस्था की जाय और उनको वित्तीय संस्थानों और हुडको से मदद दिलायी जाये तथा उनका 50 हजार से एक लाख रुपये विशेष रूप से दिलाये जांय, कर्ज के तौर पर बिना सूद के दिलाये जांये। वन विभाग की ओर से बांस और अन्य चीजें देने के लिये विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। इसमें भारत सरकार को पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और इसमें भारत सरकार की पूरी मदद होनी चाहिये तथा उसको स्थिति का पूरा जायजा लेना चाहिये। प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति जो सहानुभूति दिखाई है उसके अनुरूप बिहार की सरकार को वहां पर काम करना चाहिये और बाढ़ और भूकंप से प्रभावित जो उत्तरी बिहार के इलाके हैं उनको फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जानी चाहिये ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. S. P. Malaviya—Absent. Mr. Narayanasamy. Inadequate Allotment of j early Budget for Jawaharlal Nehru Institute of Posi-Ciradu-ate Medical Education and Research. (Jipmer) Pondicherry

SHRl V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam Deputy Chairman, I thank you very much for giving mc this opportunity to raise a very important issue of the health problem in the Southern part of the country. The Jawaharlal Nehru Institute of Post-graduate Medical Education and Research (JIPMER; which is located in Pondicherry is one of the best institutes in Asia. It was opened by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1965. This institute comprises medical education department, research department and diseases curing department. This institute is one of the prestigious institutes of this country. Of late, for the past three years JIPMER hospital has been neglected. The yearly budget for this hospital and research institute was Rs. 10 crores. There are more than 3000 out-patients coming from the Southern part of the country[1] to this hospital for treatment. Every day more than 1000 people are being treited regularly as in-patients in that hospital. For the past three years medicines are not available. The in-patients have been directed by the JIPMER to purchase medicines from the market. Even out-patients have also not been given the medicines. What was the reason for this ? The JIPMER authorities say that tne budget allocation which was Rs. 10 crores per year has been reduced to Rs. 5 tiores whereas post-graduate Institute of Medical Sciences Chandigarh has been allocated Rs. 10 crores. All India Institute of Medical Sciences has been given more than Rs. 20 crores but this prestigious institute which is serving the people of this country, which is doing research work, which is carrying out research in medicines and surgery and which is tak-in£ care of such other aspects as Postgraduate institute does, has not been considered. Madam, another important thing is that there are no sufficient doctors in the hospital. Even for teaching purposes, the professors are nut there. In 1986, there was a ucstion put by one of the hon. Members in this House and the then Health Minister gave an assurance before this House that all the pests will be filled up within a period of six months. Madam, more than two vears have elapsed, nearly *65* percent of the posts of doctors and professors are lying vacant as on date. The doctors and the professors come there because there is a quota for their children. They get admission for their children there aid then go away from that institute. There are more doctors available in the Southern part of the country. The JIPMER authorities can fill up these posts